**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3225**
**12.07.2019 को उत्तर के लिए**

**जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य-योजना**

**3225. श्री तेजस्वी सूर्याः**

**क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने पूरे भारत विशेषकर उत्तर और मध्य भारत में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि को देखते हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनएपीसीसी) को संशोधित करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक में आज की तिथि तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य, आवंटित बजट और अनुमोदित निधियां कितनी है?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) और (ख) : सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे आठ मिशनों में, पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के अनुरूप संशोधन लाने हेतु कार्रवाई आरंभ की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्यों को लू लगने से बचाव और उसके प्रबंधन के संबंध में कार्य-योजना तैयार करने हेतु अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत, 2017 को तुलना के लिए आधार वर्ष के रूप में रखते हुए, वर्ष 2024 तक विविक्त कण (PM) $PM_{2.5}$ और PM10 की सांद्रता में 20-30% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनसीएपी के तहत, परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए ऐसे 102 शहरों की सूची तैयार की गई है जहां इन विविक्त कणों की सांद्रता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक दर्ज़ की गई है। इनमें से, दस लाख से अधिक आबादी वाले और 90µg/m3 से अधिक $PM_{10}$ स्तरों वाले ऐसे 28 शहरों को अभिज्ञात किया गया है जहां प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना अपेक्षित है। कर्नाटक राज्य के चार शहर, नामतः बेंगलुरू, दावणगेरे, गुलबर्गा और हुबली-धारवाड़ उन 102 शहरों की सूची में शामिल हैं जहां वायु की गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। आज की तिथि के अनुसार, बेंगलुरू के लिए 10 करोड़ रूपये, दावणगेरे के लिए 20 लाख रूपये और गुलबर्गा तथा हुबली-धारवाड़ के लिए प्रति शहर 10 लाख रूपये के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है।

****